

वेतन में से कटौती द्वारा राजनीतिक योगदान। उम्मीदवारों को योगदान। पहल अधिनियम।

- यूनियनों को वेतन में से कटौती किए गए धन को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित करता है। कार्पोरेशनों या सरकारी ठेकेदारों द्वारा वेतन में से कटौतियों, यदि कोई हों, पर इस्तेमाल के वही प्रतिबंध लागू करता है।
- नियोजित-प्रायोजित समिति या यूनियन में स्वैच्छिक रूप से किए गए कर्मचारी योगदानों की अनुमति देता है यदि वार्षिक रूप से, लिखित रूप में प्राधिकृत किया जाता है।
- यूनियनों और कार्पोरेशनों को उम्मीदवारों और उम्मीदवार द्वारा नियंत्रित समितियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान देने से प्रतिबंधित करता है।
- अन्य राजनीतिक खर्चें अप्रतिबंधित रहते हैं, जिन में उपलब्ध संसाधनों से कार्पोरेट खर्चें शामिल हैं जो वेतन से कटौती पर प्रतिबंध द्वारा सीमित नहीं किए गए हैं।
- निर्वाचित अधिकारियों या अधिकारी द्वारा नियंत्रित समितियों में सरकारी ठेकेदार के योगदानों को प्रतिबंधित करता है।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव के बारे में वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- उपाय की ज़रूरतों को लागू करने और बाध्य करने के लिए, राज्य और स्थानीय सरकार के लिए बढ़े हुए खर्चें—संभावित रूप से \$1 मिलियन सालाना से अधिक।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

राजनीतिक सुधार अधिनियम। कैलिफोर्निया का 1974 राजनीतिक सुधार अधिनियम मतदाताओं द्वारा अपनाया गई पहल है जिसको राज्य के अभियान वित्त और प्रकटीकरण कानून द्वारा स्थापित किया गया था। यह अधिनियम राज्य और स्थानीय उम्मीदवारों, मतदान उपायों और अधिकारियों पर लागू होता है, लेकिन संघीय उम्मीदवारों या अधिकारियों पर लागू नहीं होता है। राज्य का फेयर पॉलिटिकल प्रेक्टिसिज कमीशन (FPPC) (1) इस अधिनियम की आवश्यकताओं को लागू करता है, जिसमें कथित उल्लंघन की जांच करना शामिल है, और (2) अधिनियम की FPPC की व्याख्या के बारे में सलाह और राय को जारी करके जनता के लिए प्रशासनिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।

स्थानीय अभियान वित्त कानून। इस अधिनियम द्वारा स्थापित आवश्यकताओं के अलावा, कुछ स्थानीय सरकारों के पास स्थानीय उम्मीदवारों, मतदान उपायों और अधिकारियों के लिए अभियान वित्त और प्रकटीकरण आवश्यकताएं हैं। इन अध्यादेशों को स्थानीय सरकार द्वारा लागू स्थापित किया गया है।

राजनीतिक खर्च। कई व्यक्ति, समूह और व्यवसाय राज्य के और स्थानीय उम्मीदवारों या मतदान उपायों का विरोध या समर्थन करने के लिए पैसे खर्च करते हैं। यह राजनैतिक खर्च कई प्रकार से हो सकता है, जिसमें उम्मीदवारों या समितियों के लिए पैसे का योगदान, अभियानों के लिए दान और राय का संवाद करने के लिए विज्ञापनों का निर्माण करना शामिल हैं। राज्य अभियान वित्त कानून के तहत, तीन प्रकार का राजनीतिक खर्च होता है:

- **राजनीतिक योगदान।** शब्द राजनीतिक “योगदान” में आमतौर पर पैसे, माल या सेवाएं (1) सीधे किसी उम्मीदवार को,

(2) उम्मीदवार के अनुरोध पर या (3) किसी समिति को देना शामिल है जो इन संसाधनों का उपयोग किसी उम्मीदवार या मतदान उपाय का विरोध या समर्थन करने के लिए करती है। वर्तमान कानून उस राजनीतिक योगदान की राशि को, जो व्यक्ति, समूह और व्यवसाय किसी राज्य के उम्मीदवार (या समिति, जो किसी राज्य के उम्मीदवार को पैसे देती है) को दे सकते हैं, को सीमित करते हैं। 2012 में, उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति, समूह या व्यापार गवर्नर पद के लिए उम्मीदवार को \$26,000 तक और विधायी कार्यालय के लिए किसी उम्मीदवार को \$3,900 तक का योगदान कर सकता था। इसके अलावा, मौजूदा कानून की आवश्यकता है कि राजनीतिक योगदान का खुलासा राज्य या स्थानीय चुनाव अधिकारियों को किया जाए।

- **स्वतंत्र व्यय।** किसी उम्मीदवार या मतदान उपाय को समर्थन या विरोध का संचार करने के लिए खर्च को आमतौर पर एक स्वतंत्र खर्च माना जाता है, और अगर धन को एक ऐसे तरीके से खर्च किया जाता है जो इनके साथ समन्वित नहीं हैं (1) कोई उम्मीदवार या (2) किसी उम्मीदवार या मतदान उपाय का समर्थन या विरोध करने के लिए स्थापित समिति। उदाहरण के लिए, किसी उम्मीदवार “के लिए मतदान” करने के लिए मतदाताओं से आग्रह करने के लिए कोई टेलीविजन विज्ञापन तैयार करना एक स्वतंत्र व्यय है अगर विज्ञापन को उम्मीदवार के अभियान के साथ बिना कोई समन्वय करे तैयार किया जाता है। वर्तमान कानून उस पैसे की राशि को सीमित नहीं करते हैं जिसे व्यक्ति, समूह, और कारोबार स्वतंत्र व्यय पर खर्च कर सकते हैं। हालाँकि, इन व्ययों का खुलासा चुनाव अधिकारियों को किया जाना चाहिए।

- **अन्य राजनीतिक खर्च।** कुछ राजनीतिक खर्च को एक राजनीतिक योगदान या एक स्वतंत्र खर्च नहीं माना जाता है। इस व्यापक श्रेणी में “सदस्य संचार”—किसी संगठन द्वारा अपने सदस्यों, कर्मचारियों, या शेरधारकों को राजनीतिक पृष्ठानक का संवाद करने में खर्च शामिल है। इस खर्च पर राज्य के कानून द्वारा कोई सीमा नहीं है और चुनाव अधिकारियों को इसका खुलासा करने की जरूरत नहीं है।

वेतन कटौतियाँ। सीमित परिस्थितियों के तहत, नियुक्ता किसी कर्मचारी के वेतन चेक में से पैसे रोक सकते हैं। रोके गए धन को “वेतन में कटौती” कहा जाता है। कुछ आम वेतन कटौतियों में सामाजिक सुरक्षा, आय कर, चिकित्सा योजनाओं, और स्वैच्छिक धर्मार्थ योगदान के लिए कटौती शामिल हैं।

यूनियनों के देय और शुल्क। कैलिफोर्निया में लगभग 2.5 मिलियन श्रमिकों का श्रमिक यूनियनों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। यूनियनों सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसके द्वारा वे नियुक्ताओं के साथ रोजगार के नियम और शर्तों पर बातचीत करते हैं। आमतौर पर, यूनियनों अपनी गतिविधियों के लिए इनसे एकत्र किए गए पैसे से भुगतान करती हैं (1) यूनियन के सदस्यों से ली गई राशि और (2) यूनियन के गैर-सदस्यों द्वारा भुगतान किया गया फेयर शुल्क, जिनका प्रतिनिधित्व सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में यूनियन द्वारा किया जाता है। कई मामलों में, नियुक्ता स्वतः ही अपने कर्मचारियों के वेतन में से इन देयों और शुल्क को घटा देते हैं और यूनियनों के लिए पैसे का हस्तांतरण कर देते हैं।

राजनीतिक खर्च के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल वेतन कटौती। कई यूनियनों वेतन कटौती से प्राप्त होने वाली इस निधि का इस्तेमाल उन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए करती हैं जो सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया के साथ सीधे संबंधित नहीं हैं। इन व्ययों में राजनीतिक योगदान और स्वतंत्र व्यय शामिल हैं—और साथ ही यूनियन के सदस्यों को राजनीतिक विचारों का संवाद करने में खर्च भी शामिल है। यूनियन के गैर-सदस्य अपने फेयर शेर शुल्क का इस्तेमाल इस राजनीतिक खर्च के लिए न करने का विकल्प दे सकते हैं और अन्य खर्च से भी जो सामूहिक सौदेबाजी से संबंधित भुगतान के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। यूनियनों के अलावा, अपेक्षाकृत कुछ संगठन वर्तमान में वेतन कटौतियों का उपयोग कैलिफोर्निया में राजनीतिक खर्च के वित्तपोषण के लिए करते हैं।

प्रस्ताव

यह उपाय निम्न के द्वारा राज्य और स्थानीय अभियान खर्च को सीमित करने के लिए राज्य अभियान वित्त कानूनों में परिवर्तन करता है:

- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की श्रमिक यूनियनों
- निगम।
- सरकारी ठेकेदार।

ये प्रतिबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और कांग्रेस के सदस्यों जैसे संघीय कार्यालयों के लिए अभियान खर्च को प्रभावित नहीं करते हैं।

वेतन कटौती का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए खर्च का वित्तपोषण करने पर रोक लगाता है। यह उपाय यूनियनों, निगमों, सरकारी ठेकेदारों, और राज्य और स्थानीय सरकार के नियुक्ताओं को किसी कर्मचारी के वेतन में से काटे गए पैसे को “राजनीतिक उद्देश्यों” के लिए खर्च करने से प्रतिबंधित करता है। इस उपाय के तहत इस शब्द में राजनीतिक योगदान, स्वतंत्र व्यय, अभियानों से संबंधित सदस्य संचार और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अन्य व्यय शामिल हैं। यह उपाय यूनियनों के वेतन में से कटौती का इस्तेमाल अन्य गतिविधियों के लिए भुगतान करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें सामूहिक सौदेबाजी और संघीय अभियानों में राजनीतिक खर्च शामिल हैं।

निगमों और यूनियनों द्वारा राजनीतिक योगदान करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह उपाय उम्मीदवारों को निगमों और यूनियनों द्वारा योगदान को प्रतिबंधित करता है। यही कारण है कि वे इनको योगदान नहीं कर सकते हैं (1) सीधे उम्मीदवारों को (2) उन समितियों को जो उम्मीदवारों के लिए योगदान करती हैं। यह निषेध, तथापि, किसी निगम या यूनियन की स्वतंत्र व्यय पर पैसे खर्च करने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है।

निर्वाचित अधिकारियों के लिए योगदान करने के सरकारी ठेकेदारों के प्राधिकरण को सीमित करता है। यह उपाय सरकारी ठेकेदारों (सामूहिक सौदेबाजी के ठेके वाले सार्वजनिक क्षेत्र की श्रमिक यूनियनों सहित) उन निर्वाचित अधिकारियों को, जो उनके ठेके देने में भूमिका निभाते हैं, योगदान करने पर प्रतिबंध लगाता है। विशेष रूप से, सरकारी ठेकेदार उस समय निर्वाचित अधिकारियों उस समय से लेकर, जब उनका अनुबंध विचारार्थ हो, अनुबंध समाप्त होने की तारीख तक योगदान नहीं कर सकते।

वित्तीय प्रभाव

राज्य में कानून के कथित उल्लंघन की जांच करने और सलाह के लिए अनुरोध करने की लागत में वृद्धि का अनुभव होगा। इसके अलावा, राज्य और स्थानीय सरकारों को कुछ अन्य बड़ी हुई प्रशासनिक लागत का अनुभव होगा। संयुक्त रूप से, इन लागतें **सालाना \$1 मिलियन** से अधिक हो सकती हैं।